

# नवा भारत



5

66 गिरफ्तारियों में 45 गैर-श्रमिक



6

नवाचार और युवाओं के लिए नया आकाश



7

भारत का निर्यात 860 अरब डॉलर रिकॉर्ड



8

खलील अहमद आईपीएल से हुए बाहर

## बिल को राजनीतिक रंग न दें : पीएम

मेरी गारंटी है - निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी

विरोध करने वालों को महिलाओं ने माफ नहीं किया  
'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर लोकसभा में चर्चा

नई दिल्ली, 16 अप्रैल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि हम देश को नई दिशा देने जा रहे हैं. ये 21वीं सदी का सबसे अहम बिल है.

उन्होंने कहा कि राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय की समाज की मन स्थिति और नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैप्चर कर एक राष्ट्र की अमानत बना देती है. एक मजबूत धरोहर तैयार करती है. भारत के संसदीय इतिहास में ये बेसा ही पल है. महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिक्र-जिसने विरोध किया है, महिलाओं ने उसे माफ नहीं किया है. संसद के विशेष सत्र में गुरुवार



को हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी लोकसभा में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आवश्यकता तो ये थी कि 25-30 साल पहले, जब वे विचार सामने आया तभी इसे लागू कर देते. आज हम इसे काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते. आवश्यकतानुसार उसमें समय-समय पर सुधार होते और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने अपील में कहा कि इस बिल को राजनीतिक रंग न दें.

### संसद में प्रियंका गांधी ने की आरोपों की बौछार

वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस महिला सांसदों के लिए आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन बहस इस पर नहीं बल्कि इस तथ्य पर है कि इस विधेयक में राजनीति की बू आ रही है. महिलाओं के लिए आरक्षण का कदम वास्तव में केंद्र की एनडीए सरकार का पॉलिटिकल ट्रूप काई है, जिसके जरिए वह चुनावों में लाभ लेना चाहती है. प्रियंका ने महिलाओं के आरक्षण के लिए पिछली कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों का खाका पेश किया. उन्होंने कहा कि देश में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं की 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान सबसे पहले राजीव गांधी की सरकार ने पेश किया था, लेकिन उस वक्त वह पारित नहीं हो पाया था. उन्होंने बीजेपी पर इस आरक्षण का विरोध करने का आरोप लगाया. प्रियंका ने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने उस आरक्षण बिल का जिक्र किया, लेकिन हमेशा की तरह आधी बात ही बताई.



### चाणक्य आज जिंदा होते तो वो भी चौक जाते...

लोकसभा में गुरुवार को महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मजाकिया अंदाज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक तंज कसा, जिसे सुनकर वह भी अपनी हसी नहीं रोक पाए. उन्होंने कहा कि आज चाणक्य अगर आज जिंदा होते तो वो भी चौक जाते, आपकी कुटिलता को दाद देते.

### एक नजर में 15 लाख की रिश्त के मामले में केस दर्ज

मुंबई. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने महाराष्ट्र में 15 लाख रुपये की कथित रिश्तखोरी के मामले में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के एक अधीक्षक और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की पहचान सीजीएसटी टागों, ग्रामीण, आयुक्तालय के तत्कालीन अधीक्षक मोहित शर्मा, एक निजी फर्म के मालिक उदय शिवराज कोंशेट्टी और एक निजी व्यक्ति किरण व्यास के रूप में हुई है. सीबीआई की मुंबई रिश्त अधिचार निरोधक शाखा की दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, यह मामला कर संबंधी मामलों में अविधे नकद निपटान और भ्रष्टाचार के आरोपों वाली एक शिकायत का था. आरोप है कि मोहित शर्मा ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर एक आपराधिक कार्यों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है. मामले की सुनवाई सीजीएसटी सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बाघची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने. सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि इन बातों को लेकर इतना भयवृत्त होने की जरूरत नहीं है. आपका विचार अच्छा है, आपने अपनी बात रख दी है. अब यह संबंधित अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे क्या फैसला लेते हैं.

### मतदान करने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते

#### अनिवार्य मतदान की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली, 16 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अनिवार्य मतदान लागू करने के निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया.

याचिकाकर्ता ने कहा था कि जो लोग मतदान करने से इनकार करते हैं, उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए. न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि चुनावों में भागीदारी को दमनकारी या बाध्यकारी उपायों से लागू नहीं कर सकते.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाला बाघची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों से मताधिकार प्रयोग करने की अपेक्षा होती है, लेकिन राज्य किसी व्यक्ति को वोट देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. याचिकाकर्ता के वकील ने सुझाव दिया था कि अदालत चुनाव



आयोग को अनिवार्य मतदान के लिए दिशा-निर्देश बनाने और बिना वैध कारण वोट न देने वालों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दे. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि मताधिकार के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, लेकिन हम इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते.

न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उठाए गए मुद्दे नैतिक दायरे में आते हैं और इन पर उचित विधायी और कार्यकारी अधिकारियों (संसद और सरकार) द्वारा विचार किया जाना ही सबसे बेहतर है. पीठ ने दोहराया कि मतदान एक संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक कर्तव्य है, लेकिन इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता.

### अशोक चक्र पर गाइडलाइंस बनाने की मांग पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पर अशोक चक्र के प्रदर्शन को लेकर गाइडलाइंस बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने साफ किया कि इस तरह के मामलों में अत्यधिक भयवृत्त होने के बजाय रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है. मामले की सुनवाई सीजीएसटी सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बाघची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने. सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि इन बातों को लेकर इतना भयवृत्त होने की जरूरत नहीं है. आपका विचार अच्छा है, आपने अपनी बात रख दी है. अब यह संबंधित अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे क्या फैसला लेते हैं.

### चीथे और पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का भी डीए बढ़ा

#### प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल. राज्य शासन ने उपक्रमों, निगमों, मंडलों एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया है. इस फैसले से चौथे एवं पांचवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा. राज्य शासन द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है. संशोधित दरों के अनुसार पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 323 प्रतिशत तथा चौथे वेतनमान के कर्मचारियों का 146.5 प्रतिशत हो जाएगा. यह वृद्धि एक जुलाई 2025 से प्रभावशील मानी जाएगी.

### अमेरिका ने होर्मुज जलमार्ग में 10 जहाजों को वापस भेजा

#### ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में व्यापार को ठप करने की दी चेतावनी

एजेंसी, 16 अप्रैल. होर्मुज जलमार्ग को लेकर अमेरिका और ईरान एक-दूसरे के सामने हैं. अमेरिका को सेना ने कहा कि उन्होंने ईरानी पोर्ट से निकल रहे 10 जहाजों को रोका और उन्हें वापस भेज दिया. अमेरिकी सेना ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. अमेरिका ने होर्मुज जलमार्ग की नाकाबंदी कर रखी है.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने एक्स पर लिखा, सोमवार से अमेरिका की नाकाबंदी के बाद एक भी जहाज होर्मुज पार नहीं कर सका है और हमने कम से कम 10 जहाजों को



वापस भेजा है. हालांकि अमेरिकी सेना ने जहाजों की संख्या भी बताई थी, लेकिन आगे यह भी बताया कि 10वें जहाज को अमेरिका के एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर द्वारा वापस ईरान की ओर मोड़

### अमेरिका-ईरान शांति समझौते के करीब पहुंचे

सूत्रों के अनुसार अमेरिका और ईरान 21 अप्रैल को खत्म हो रहे सीजफायर से पहले समझौते के करीब पहुंच रहे हैं. अमेरिकी मीडिया के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच बातचीत आगे बढ़ी है, हालांकि कुछ मतभेद अब भी बाकी हैं.

ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने धमकी दी कि अमेरिका उन फिलिपिन संस्थानों पर सेकेडरी सैंक्शन लगाकर ईरान पर आर्थिक दबाव को और बढ़ाने जा रहा है.

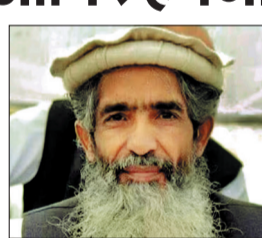
### लश्कर चीफ आमिर हमजा को मारी गोली

#### लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने किया हमला

भारत में हुए कई हमलों का मास्टर माइंड है हमजा

#### इस्लामाबाद, 16 अप्रैल. पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक सदस्यों में से एक आमिर हमजा को लाहौर में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी है, उसे फिलहाल एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमलावरों ने लाहौर में एक न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर उन पर फायरिंग की. हमला किसने और



### कौन है आमिर हमजा?

1959 में जन्मा हमजा एक बड़ा आतंकी है. एलईटी के एक शीर्ष विचारक के तौर पर वह एक जोशीली वक्ता और लेखक के रूप में जाना जाता है. एक समय उसने इस आतंकी समूह के आधिकारिक प्रकाशन का संपादन भी किया था. उसने कई किताबें भी लिखीं, जिनमें 2022 में प्रकाशित काफिला दावत और शहादत (प्रचार और शहादत का कारवां) भी शामिल हैं. हमजा ने 1985 और 1986 के बीच आतंकी हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर की स्थापना की थी. उसका नाम भारत और दुनिया भर में कई आतंकी गतिविधियों से जुड़ा रहा है. सईद के बाद उसे लश्कर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नेता माना जाता है और अमेरिका ने भी एक आतंकी घोषित किया हुआ है.

### एयरपोर्ट पर दो विमान टकराए

#### विंगटिप ने विमान के पंख को छुआ

नई दिल्ली, 16 अप्रैल. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को एक मामूली विमान हादसा सामने आया, जब स्पाइसजेट का एक विमान खड़े अकासा एयर के विमान से टकराया.

जाकारी के अनुसार, दोपहर करीब दो बजे स्पाइसजेट विमान के विंगटिप ने ग्राउंड मूवमेंट के दौरान अकासा एयर के स्थिर विमान के पंख को हल्के से छू गया. यह टक्कर बेहद हल्की थी, जिससे दोनों विमानों को मामूली नुकसान पहुंचा. प्रारंभिक जाकारी के अनुसार, अकासा का विमान उस समय स्थिर था, तभी दूसरी



एयरलाइन के विमान ने उससे संपर्क किया. सभी यात्रियों और कू मेंबर्स को सुरक्षित उतार लिया गया. एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए और दोनों विमानों की जांच शुरू कर दी गई. प्रभावित विमानों को फिलहाल सेवा से हटा दिया गया है ताकि विस्तृत तकनीकी जांच की जा सके.

### गुस्ताखी माफ

ये बार बार अपनी जात क्यों बता देते हैं ?



### उपलब्धि

#### पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का लेख किया साझा

#### सुधार-तकनीक के जरिए नए मानक स्थापित कर रहा रेलवे

प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी जानकारी नई दिल्ली, 16 अप्रैल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय रेलवे में बड़ा बदलाव आया है और यह लगातार सुधार और तकनीक के जरिए नए मानक स्थापित कर रहा है. इस संदर्भ में उन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लिखे गए एक लेख को साझा किया, जिसमें बताया कि पिछले एक दशक में स्पष्ट नीति, आधुनिक तकनीक और लगातार निवेश के



जरिए भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, भारतीय रेलवे के पूरे सिस्टम में बड़ा बदलाव आया है और इसके नतीजे साफ दिखाई दे रहे हैं. केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि यह सेक्टर कैसे सुधार और तकनीक के जरिए नए

मानक तय कर रहा है. इसमें कहा गया कि करोड़ों यात्रियों के लिए रेल यात्रा कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है. इतने बड़े नेटवर्क में सुरक्षा सिर्फ तकनीकी मामला नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे से जुड़ा मुद्दा है. लेख में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान ही 'सेफ्टी फर्स्ट' यानी सुरक्षा को सर्वोपरि रखने का स्पष्ट संदेश दिया गया था. इसी दिशा में रेलवे ने तकनीक-आधारित और लगातार निवेश वाली रणनीति अपनाकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को

मजबूत किया है. इसके परिणामस्वरूप देश में ट्रेन हादसों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है. 2014-15 में जहां 135 रेल दुर्घटनाएं हुई थीं, वहीं 2025-26 में यह घटकर सिर्फ 16 रह गईं, यानी करीब 89 प्रतिशत की कमी आई थी. यह कमी ऐसे समय में आई है जब ट्रेन संचालन और यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसी अवधि में 'कंसिक्वेशन एक्सीडेंट इंडेक्स' (प्रति किलोमीटर दुर्घटना दर) भी 0.11 से घटकर 0.01 हो गया है, जो हर किलोमीटर यात्रा के लिये सात से सिरस्टम को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित दर्शाता है. 2014-15 में रेल हादसों में 292 लोगों की जान गई थी, जबकि 2025-26 में 16 दुर्घटनाओं में 16 लोगों की ही मौत हुई. रेलवे के महत्व पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखा, हर सुबह जब भारत जागता है, तब उसकी रेलें पहले से ही चल रही होती हैं. ऑफिस जाने वाले, छात्र, प्रवासी मजदूर, परिवार और सैनिक समेत 2 करोड़ से ज्यादा यात्री प्रतिदिन ट्रेनों में सफर करते हैं.

### जुबिन नौटियाल ने रचाई शादी

#### वचन के प्यार संग सात फेरे, जुबिन की सौंठे वेंडिंग

देहरादून/मुंबई, 16 अप्रैल. बॉलीवुड के लोकप्रिय सिंगर जुबिन नौटियाल ने अपने फैस को चौंकाते हुए गुपचुप शादी कर ली है. लंबे समय से इंडस्ट्री के 'एल्लिजबल बैचलर' माने जाने वाले जुबिन ने अपने बचपन के प्यार को जीवनसाथी बना लिया है. खबरों के मुताबिक, यह शादी उत्तराखंड में बेहद निजी तरीके से संपन्न हुई, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए. हालांकि, इस शादी को लेकर अभी तक जुबिन की



आर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. दिलचस्प बात यह है कि उनकी पत्नी की पहचान भी अब तक सामने नहीं आई है, जिससे फैस की उत्सुकता और बढ़ गई है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में जुबिन अपनी पार्टनर के साथ नजर आ रहे हैं, जिससे इस खबर को और हवा मिल गई है.

### 1 लाख 81 हजार शिकायतों का निवारण

नई दिल्ली. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने बताया है कि मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा कुल 1 लाख 81 हजार 279 शिकायतों का निवारण किया गया. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के काम पर केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की गुरुवार को जारी 47वीं मासिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. विभाग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि लगातार 45वें महीने केंद्रीय सचिवालय में मासिक शिकायत निस्तारण का स्तर एक लाख मामलों से ऊपर रहा.